समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Monday, 28 September 2026

संसद का शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर तक, वोट चोरी और विदेश नीति पर गरमाएगी सियासत

Publisher

Published on 08 Nov 2025

संसद का **शीतकालीन सत्र** इस बार 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। राष्ट्रपति **द्रौपदी मुर्मू** ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री **किरन रिजिजू** ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा कि सत्र का उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सत्र रचनात्मक और सार्थक रहेगा।

शीतकालीन सत्र में कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे चर्चा में आएंगे। इसमें **वोट चोरी**, **देश की विदेश नीति**, **आर्थिक सुधारों** और **सामाजिक नीतियों** पर गहन बहस होने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि सत्र में राजनीतिक दल अपने मुद्दों और एजेंडों को लेकर पूरी सक्रियता से संसद में मौजूद रहेंगे।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में कहा, *“[illegible] 1 [illegible] 19 [illegible], [illegible]”*

संसद का यह सत्र कई मायनों में अहम माना जा रहा है। बीते समय में हुए राजनीतिक घटनाक्रम और नए विधेयकों पर चर्चा के लिए यह सत्र महत्वपूर्ण है। सत्र में विभिन्न मंत्री और सांसद अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर विचार रखेंगे और प्रस्तावों पर बहस करेंगे।

विशेषज्ञों के अनुसार, **वोट चोरी** जैसे विवादास्पद मुद्दे इस सत्र में गर्म चर्चा का केंद्र बन सकते हैं। इसके साथ ही भारत की **विदेश**

नीति, सीमा सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर भी बहस होने की संभावना है। सांसद इस सत्र में नए बिलों और संशोधनों पर विचार-विमर्श करेंगे, जिससे देश की नीतियों और कानून व्यवस्था में सुधार हो सके।

सत्र की अवधि 1 से 19 दिसंबर तक है, लेकिन यह संसदीय कार्यों की आवश्यकता अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर बहस लंबी होती है या जरूरी बिलों पर ज्यादा समय लगता है, तो सत्र को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

पिछले वर्षों के अनुभव से यह भी देखा गया है कि शीतकालीन सत्र में विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच बहस और विरोध-प्रत्यावेदन अधिक देखने को मिलता है। इस बार भी राजनीतिक दलों की रणनीति और संसद में उनके कदमों पर नजर रहेगी। सांसद विधायकों के लिए यह समय अपने मतदाताओं के हितों को संसद में प्रमुखता से उठाने का अवसर भी माना जा रहा है।

संसद का यह सत्र न केवल राजनीति के लिहाज से अहम है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक नीतियों के लिए भी निर्णायक साबित हो सकता है। इसमें नए सरकारी कार्यक्रमों, वित्तीय बजट संशोधनों और विकास योजनाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है।

इस सत्र के दौरान आम जनता भी संसद की कार्यवाही पर ध्यान देगी, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे चर्चा में होंगे जो सीधे उनके जीवन और समाज पर असर डालते हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह सत्र **वोट चोरी, विदेश नीति और आर्थिक सुधारों** के मामले में निर्णायक साबित हो सकता है।

शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में पेश होने वाले सभी विधेयकों और प्रस्तावों पर बहस और मतदान होगा। यह सत्र देश की राजनीतिक दिशा और नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने वाला माना जा रहा है। सभी सांसद इस सत्र में अपनी सक्रियता और रणनीति के साथ हिस्सा लेंगे, जिससे देश की राजनीति में हलचल बनी रहेगी।

इस प्रकार, 1 से 19 दिसंबर तक चलने वाला संसद का शीतकालीन सत्र राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर बहस का महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जनता और विश्लेषक इसे बड़े ध्यान और उत्साह के साथ देख रहे हैं, क्योंकि यह सत्र आने वाले समय में देश की दिशा और नीति निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाएगा।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.